आकाशवाणी शिमला

23.07.2024 **1945बजे**

'' मुख्य समाचार''

- केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में 2024–25 का बजट किया पेश–बजट में युवाओं के रोजगार और कौशल विकास पर बल।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय बजट को देश के चहुमुखी विकास व विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करने वाला दिया करार।
- भाजपा ने केन्द्रीय बजट को सराहा–कांग्रेस ने बताया निराशाजनक।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों के विलय की सम्भावनाएं तलाशने के अधिकारियों को दिए निर्देश।

बजट

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में एन.डी.ए. सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में दो लाख करोड रुपये के परिव्यय से पांच वर्ष की अवधि में चार करोड से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढाने की पांच योजनाओं और पहल के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की गई। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन पचास हजार रुपये से बढाकर 75 हजार रुपये करने की घोषणा की। बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कम्पनियों पर कॉरपोरेट कर दर चालीस प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए दो लाख 66 हजार करोड रुपये के प्रावधान की घोषणा की। निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगले दो वर्ष में प्रमाणन और ब्रैंडिंग समर्थित प्राकृतिक खेती में एक करोड किसानों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार, जनजातीय समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी।

बजट में महिला नीत विकास को बढावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर तीन लाख करोड रुपये से अधिक का आबंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार एक करोड शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए दस लाख करोड रुपये का निवेश करेगी। वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में तीन से सात लाख रुपये तक 5 प्रतिशत कर का प्रावधान किया है। तीन लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। सात से दस लाख रुपये तक की आमदनी वालों के लिए 10 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री–बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024–2025 विकसित भारत के लिए है जो चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करता है, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय बजट पर एक वीडियो संदेश में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। यह देश के लिए बेहतर विकास और उज्ज्वल भविष्य लेकर आया है।

नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा है कि केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बजट को दूरदर्शी, सर्व–स्पर्शी व सर्व–समावेशी होने के साथ गरीब, महिला, युवा व अन्नदाता वर्ग के कल्याण को चरितार्थ करने और उद्योग व अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने वाला बताया है।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट को आत्म निर्भर और विकसित भारत की आधारशिला को सुदृढ़ करने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और अन्य जरूरतमंद समूहों के सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत प्रभावी होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में केन्द्र से मिली सहायता प्राकृतिक

आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण व राहत कार्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अनुराग ठाकुर ने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हिमाचल में क्षतिपूर्ति के लिए विशेष सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार जताया है। इस बीच सांसद सिकंदर कुमार ने कहा है कि बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे ले जाएगा।

भाजपा प्रतिक्रिया

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विकसित भारत के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में मील पत्थर साबित होगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान के पुनर्निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया सहयोग प्रदेश के लोगों के लिए मददगार साबित होगा। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केन्द्रीय बजट गरीब कल्याण, महिला, युवा उत्थान और किसान कल्याण का बजट है। बिंदल ने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में आई आपदा को लेकर भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। वहीं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा है कि आम बजट 2024 विकास से प्रेरित है और ये देशवासियों की आशाओं व अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है।

प्रतिक्रिया–कांग्रेस

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आज प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि केन्द्रीय बजट में हिमाचल के हितों की अनदेखी हुई है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हिमाचल में हुई आपदा में पुर्नवास के लिए सहायता की बात की गई है। लेकिन इसमें भी भेदभाव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत और पुर्नवास के लिए केन्द्रीय बजट में हिमाचल, सिक्किम और उत्तराखण्ड का जिक्र किया गया है और हिमाचल को बजट में अलग से कुछ भी नहीं मिला है।

इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी केंद्रीय बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा है कि बजट अपेक्षा के अनुरूप नही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बजट में हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिये कुछ भी नही है और प्रदेश के बागवानों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूंजीवाद को बढ़ावा देगा और इससे अमीर व गरीब के बीच की खाई बढ़ेगी। वहीं राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी केन्द्रीय बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल के सेब बागवानों के हितों की अनेदखी की गई है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शिमला में आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022–2023 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जहां विद्यार्थियों की संख्या एक लाख 30 हजार 4 सौ 66 थी वहीं वर्ष 2023–24 में यह संख्या घटकर 49 हजार 2 सौ 95 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 89 प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों की कम संख्या वाले विद्यालयों को विलय करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को विलय करने के कदम से पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दी जा सकेगी। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

सर्वोच्च न्यायालय–नीट

सर्वोच्च न्यायालय ने नीट–यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से इन्कार किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस संबंध में दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर

- केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में 2024–25 का बजट किया पेश–बजट में युवाओं के रोजगार और कौशल विकास पर बल।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय बजट को देश के चहुमुखी विकास व विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करने वाला करार दिया।
- भाजपा ने केन्द्रीय बजट को सराहा–कांग्रेस ने बताया निराशाजनक।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों के विलय की सम्भावनाएं तलाशने के अधिकारियों को दिए निर्देश।